काम की खबरें

हरियाणा के लेखकों, कवियों को डाला दाना

हरियाणा साहित्य अकादमी हर ज़िले की ऐसी डायरेक्टरी प्रकाशित करने जा रहा है, जिसमें उस ज़िले के साहित्यकारों के नाम, पते, फ़ोन नंबर, फोटो और उनकी प्रसिद्ध रचनाओं को शामिल किया जाएगा। सरकार की यह कोशिश लेखकों और कवियों को उसके पक्ष में खड़ा करेगी। तमाम नौसिखिए लेखक, कवि भी इसमें अपना नाम डलवाने के लिए हाथ-पैर मारेंगे। बेहतर होगा कि यही काम कोई प्राइवेट संस्था या एनजीओ संभाल ले।

अर्जुन खिलाड़ियों को अब बीस हज़ार

हरियाणा के अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों को अब 5000 रुपये मासिक भत्ते की बजाय 20 हजार मासिक मिलेंगे। हालाँकि सरकार अभी तक न तो सारे खिलाड़ियों को नौकरी दे सकी है और न ही उन्हें मेडल के बदले घोषित की गई राशि ही मिली है। लेकिन इससे इतना जरूर होगा कि हरियाणा का कोई अर्जुन अवार्डी अपना अवार्ड वापस नहीं करेगा।

आठवीं तक आनलाइन पढ़ाई

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड-19 महामारी के चलते पहली से आठवीं कक्षा तक के लिए फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर (ङ्क्रस्क्र) एप्प के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय प्रात- 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

राई स्पोर्ट्स स्कूल में आवेदन

मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, राई (सोनीपत)में कक्षा चौथी में प्रवेश हेतु शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी 2021; लेट फीस के साथ 29 जनवरी अधिक जानकारी स्कूल की वेबसाइट mnssrai.com पर उपलब्ध।

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लभगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. राम खिलावन - बल्लभगढ़ बस स्टैंड के सामने

सावधान, वारंटी के नाम पर मारुति करती धोखा, न्याय के नाम पर अन्याय व्यवस्था

ग्वालियर (ममो): नवम्बर 2019 में ग्वालियर निवासी उपेन्द्र भदौरिया ने ग्वालियर, फूल बाग स्थित मारुति डीलर प्रेम मोटर्स से मारुति की ब्रीजा कार खरीदी जिसकी कंपनी द्वारा दी गई वारंटी 2 साल व चालीस हजार किलोमीटर थी। उपेन्द्र पेशे से एक सैनिक हैं और बीएसएफ टेकनपुर ग्वालियर में तैनात हैं। अचानक गाड़ी खराब हुई और वारंटी पीरीयड में होने के नाते सर्विस सेंटेर भेज दी। मारुति के सर्विस सेंटर ने जांच के नाम पर 7 दिन निकालने के बाद उपेन्द्र को बताया कि उनकी गाड़ी का इंजन सीज हो गया है और उसमे गलती मारुति कंपनी की नहीं है। इंजन सीज होने के पीछे कंपनी ने गाड़ी में इस्तेमाल किये गए तेल की गुणवत्ता पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने लैब में टेस्ट किया है, जो तेल उपेन्द्र ने अपनी गाड़ी में इस्तेमाल किया है वह घटिया क्वालिटी का है।

उपेन्द्र ने कंपनी से पूछा कि घर की बाकी गाड़ियों में भी तो तेल उसी पेट्रोल पंप से डाल जाता है तो वह क्यों नहीं खराब होतीं? वहीं पेट्रोल पम्प मालिक ने मारुति को चुनौती दी है कि वह उसके तेल में कमी है इसे सिद्ध करे।

अब कुल जमा कंपनी ने उपेन्द्र को ऑफर दिया है कि गाड़ी इंजन बनवाई की 70 प्रतिशत

उपेन्द्र भदौरिया

रकम कंपनी गुडविल के तौर पर दे देगी और बाकी बची 30 प्रतिशत रकम उपेन्द्र को देने होंगे जो लगभग 40 हजार हैं। परेशान होकर उपेन्द्र ने अपने एक मित्र को फोन किया जिसने उन्हे उपभोक्ता कोर्ट जाने की सलाह दी है। कोर्ट के नाम पर उपेन्द्र को बिल्कुल भरोसा नहीं कि वहाँ न्याय मिलेगा और यदि मिलेगा भी तो किस कीमत पर। क्योंकि गाड़ी बिना सभी काम अटके पड़े हैं और कोर्ट के चक्कर कितने साल चलेंगे इसका कुछ अंदाज ही नहीं।

कुछ लोगों को लगता है कि उपेन्द्र जैसे सैनिक के साथ कंपनी धोखा कर सकती है पर किसी बहुत समझदार और कानून के ज्ञात के साथ नहीं। इस भ्रम में कई सरकारी अधिकारी जैसे आईपीएस और आईएएस भी होंगे, क्योंकि समाज इन्हे लेकर ऐसा ही सोचता है। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिशनर रंजीत नारायण के साथ वर्षों पूर्व ठीक इसी प्रकार की घटना मारुति गुड़गाँव में घटी। घटना के समय रंजीत नारायण केरल में तैनात थे और उन्हे भी कंपनी से वारंटी पाने के लिए हरियाणा के एक कद्दावर आईपीएस से पैरवी कर कंपनी पर दबाव बनवाना पड़ा।

कृषि कानून के खिलाफ होने वाले किसान आंदोलन में एक बड़ा कारण अनुबंध कृषि भी है। जहां एक तरफ किसान अनुबंध कृषि से जुड़े नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार और सरकार द्वारा पोषित मीडिया अनुबंध की व्यवस्था को बेहतर बताते हुए यह भी दलील दे रही है कि कान्ट्रैक्ट खेती पहले से ही चलती आ रही है तो अब उसका विरोध क्यों? सरकार की यह बात सही है परंतु विरोध क्यों का जवाब मजदूर मोर्चा की इस रिपोर्ट से सरकार और नागरिक दोनों समझ सकते हैं।

उपेन्द्र प्रशासन व्यवस्था के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति हैं तो रंजीत नारायण इसी व्यवस्था के उच्चतम पायदान के आईपीएस अधिकारी। परंतु व्यवस्था दोनों में से किसी का भी साथ न देकर सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी का साथ देती नजर आती है जिनकी जेबों में नेताओं की फौज से लेकर सभी गरम हो रहे हैं। रही सही कसर न्यायपालिकाएं पूरा कर देती हैं।

न्यायपालिका पर आम आदमी का भरोसा ही नहीं और कंपनियां खुलेआम वादाखिलाफी करती घूम रही हैं। ऐसे में कृषि बिलों पर यदि किसान न्यायपालिका नहीं जा सकता और एक एसडीएम स्तर का अधिकारी ही फैसला करने का अधिकारी होगा तो आपको बताते चलें ऐसे एसडीएम गाला डिनर में कंपनी मालिकों के जाम भरते पाए जाते रहे हैं।

किसान को तो पता है कि लिखित कान्ट्रैक्ट का लॉलीपोप और ये कानून किसके लिए हैं। खैर, कुल जमा गाड़ी खरीदते वक्त सभी जानकारी लिखित में प्राप्त करने के साथ सोचते रहे कि क्या व्यवस्था की ये सूरत बदलनी चाहिए या लिखित में लेने से भी काम चल पाएगा?

कब गिरफ्तार होगा बीपीटीपी....

पेज एक का शेष

बावजूद बिल्डर ने कोई सबक नहीं सीखा।

कब गिरफ्तार होगा काबुल चावला

बीपीटीपी के खिलाफ हरियाणा सरकार के पास असंख्य शिकायतों की भरमार है। सीएम विंडों से लेकर हरेरा, हूडा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग में बीपीटीपी के खिलाफ शिकायतें पहुंची हैं। काबुल चावला के बही खातों की जांच करा ली जाए तो यह एसआरएस से भी बड़ा प्रॉपर्टी घोटाला साबित हो सकता है। कायदे से काबुल चावला को जेल में होना चाहिए लेकिन यह शख्स फ्लैट मालिकों के पैसों से मौज उड़ा रहा है। पिछले हफ्तों प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मनाया गया जश्न यही साबित करता है। इस जश्न में हरेरा से लेकर हूडा और प्रदूषण नियंत्रण विभाग तक के अफसर शामिल हुए और उसकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर रंजीत कुमार ने बताया कि पार्क लैंड के पार्क इलीट फ्लोर्स में भी अभी तक बहुत सारे ग्राहकों को कब्जा नहीं मिला है। खुद वह भी इसके शिकार हैं। दस साल से तमाम ग्राहक अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं।

परेशान फ्लैट मालिक जो यहां कब्जा ले चुके हैं, वे अपनी जेब से पैसा लगाकर फ्लैट को रहने लायक बना रहे हैं। इस तरह उन्हें ये फ्लैट उनकी कीमत से ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं।

गुड़गांव की भी यही कहानी

बीपीटीपी से सिर्फ फरीदाबाद ही नहीं गुड़गांव के फ्लैट खरीदार भी परेशान हैं। सेक्टर 37 डी में बीपीटीपी स्पेशियो में फ्लैट बुक कराने वाले भी इसी तरह भटक रहे हैं। बीपीटीपी स्पेशियो प्रोजेक्ट 2009 में लॉन्च हुआ था। इन फ्लैटों में भी 2014 तक कब्जा दिया जाना था। अभी तक 50 फीसदी ही फ्लैट बने हैं। जिन फ्लैटों में बिल्डर कब्जे दे रहा है, उनमें सुपर एरिया बढ़ाने के नाम पर 15-20 लाख रुपये अलग से मांगे जा रहे हैं।

गुड़गांव में हरेरा का दफ्तर है। बीपीटीपी स्पेशियो के फ्लैट खरीदारों ने हरेरा में एक साल पहले बिल्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी लेकिन हरेरा ने अभी तक न कोई सुनवाई की और न ही उनकी समस्याओं का कोई समाधान निकला। दरअसल, हरेरा बिल्डरों और प्रॉपर्टी डीलरों का दलाल बनकर रह गया। यह अब सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी नहीं रही, बल्कि बिल्डरों के पक्ष में समझौते कराती है। हरेरा में कार्यरत फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) से रिटायर एक अधिकारी पूरी तरह से बिल्डरों का दलाल बनकर रह गया है। उसी के अनुसार हरेरा अब सारे फैसले ले रही है।

गतांक की चीर-फ़ाड़

पहले से कह रहा हूं, मैं तो बस चौकीदार हूं, मालिक कोई और है

डॉ. जुगल किशोर गुप्ता

मज़दूर मोर्चा के 20-26 दिसम्बर के अंक में राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक व आर्थिक समसामयिक मुद्दों पर अनेक महत्वपूर्ण समाचार व लेख प्रकाशित हुए हैं। मोदी सरकार द्वारा कोरोना आपदा को अवसर में बदलते हुए अपने पूंजीपति मित्रों की हितों की सुरक्षा हेतु तीन विवादित कृषि कानून संसद से झटपट पास करा कर किसानों पर थोंप दिए, जिसके विरुद्ध दिल्ली बॉर्डर पर लगभग एक महीने से देशव्यापी किसान आन्दोलन चल रहा है। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन तीनों कानूनों को वापिस ले और सरकार अड़ियल रूख अपनाए हुए हैं। इसलिए इनके बीच गतिरोध टूटने का नाम नहीं ले रहा है। '13 से ज्यादा राज्यों में अडानी-रिलायंस के सायलों' तथा मोनोपोली और किसान बिल' में इन कृषि कानूनों को वापिस न लेने में मोदी सरकार की मजबूरी का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। मोदी सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र व बाजार को पूंजीवादी के लिये खोल दिया गया है।

ध्यान रहे कि अडानी ग्रुप ने पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, आदि 13 राज्यों में 2.25 लाख टन से लेकर 6.75 लाख टन की स्टोरेज क्षमता के वेयरहाउस बनाए हैं तथा अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने विभिन्न शहरों में 621 रिलायंस फ्रेश व स्मार्ट स्टोर खोल रखे हैं। स्पष्ट है कि यदि मोदी सरकार इन कानूनों को वपिस ले तो उसके पूंजीपति मित्रों का भारी भरकम निवेश डूब जाएगा, इसलिए ऐसा करना सरकार के लिए मुमकिन नहीं है।

किसान आन्दोलन को लेकर मीडिया के कुछ धड़ों द्वारा एक दावे को काफ़ी हवा दी जा रही है कि दिल्ली-एनसीआर के किसान इसमें शामिल नहीं है। इस झूठे दावे का 'क्या किसान बिल असल में मज़दूर बिल है...' में दिल्ली से सटे फ़रीदाबाद के सुनपेड, साहपुर व दीघ गांवों में किसानों से बात-चीत के संदर्भ में पर्दाफ़ाश किया गया है। पलवल में दिल्ली-आगरा नेशनल हाइवे पर केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर किसानों का धरना 23 दिनों से चल रहा है, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी धर्मों के लोग शामिल हो रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉ. कफील खान की हिरासत को रद्द करने और उन्हें जेल से रिहा किए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ़ यूपी की योगी सरकार द्वारा दायर अपील पर अपने फैसले में कहा कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से दुरूस्त है, हम इस फैसले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस फैसले से योगी सरकार को तकड़ा झटका लगा है, जिसका 'बेशर्मी का इंतिहा, चपत पर चपत-डॉ कफिल खान के केस में योगी सरकार को फ़िर लगा धक्का' में खुलासा किया गया है। इस फैसले के बाद डॉ. कफील ने ट्वीट किया कि वे किसी के विरुद्ध अन्याय के खिलाफ़ कहीं भी अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे।

'पहले से कह रहा हूं, मैं तो बस चौकीदार हूं, मालिक कोई और है', 'भूख हड़ताल-तुम्हारे भूखे रहने का ही तो इंतजाम किया है' तथा '100 रुपये की बढोत्तरी-राष्ट्रवाद के लिए थोड़ा और बोझ सहन कर लो' कार्टूनों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की जन विरोधी नीतियों पर उपयुक्त तंज कसा गया है।

किसान आन्दोलन के विरुद्ध मोदी सरकार, भाजपा व संघ परिवार ने जबरदस्त प्रचार युद्ध छेड़ रखा है। वे इन आन्दोलन को टुकड़े-टुकड़े गैंग, राष्ट्रविरोधी, खालिस्तानी, आतंकवादी, वामपंथी, माओवादी, अर्बन नक्सली, पाकिस्तानी, चीन से प्रेरित, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस द्वारा भ्रमित केवल पंजाब का आन्दोलन बता कर इसकी वैधता पर सवाल उठा कर इसे अलग-थलग करना चाहते हैं। वार्ता के चक्रयुद्ध में फंसाकर सरकार इसे अधिक से अधिक लंबा खींचकर आन्दोलनकारियों को थका देने की रणनीति पर चल रही है। दूसरी तरफ़ पंजाब के बहुसंख्यक सिखों को साधने के लिये सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक बुकलेट ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सिख समुदाय के साथ संबंध-अटूट, दृढ और अडिग' प्रकाशित की है जिसे मोदी जी के सिख वेश-भूषा वाले फ़ोटो से पाट दिया गया है। 'सरकारी प्रचार: मोदी के सिखों से रिश्तों पर छपी किताब' में प्रधान मंत्री मोदी के सिखों के साथ तथाकथित अटूट सम्बन्धों की पोल खोली गई है। सिखों को प्रभावित करने के लिये 20 दिसम्बर को प्रधानमंत्री मोदी अचानक दिल्ली के गुरूद्वारा रकाबगंज में नौ वें गुरू तेग बहादुर के 400 वें जन्म दिवस पर अपने श्रद्धांजलि पेश करने के लिये पहुंच गए। लेकिन आंदोलनकारी सिख समुदाय पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

मसाले आमतौर पर इम्युनिटी बढाने का काम करते हैं, लेकिन नकली मसाले स्वास्थ्य को गंभीर नुक्सान पहुंचाते हैं। राष्ट्रवाद व स्वदेशी और शुद्ध माल की बड़ी-बड़ी बाते करने और दावे करने वाले लोग आम जनता की सेहत से खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं करते, जिसे 'राष्ट्रवादी हिंदू नेता मसाले में मिला रहा था गधे की लीद-हाथरस में पकड़ी गई, योगी के बनाये गिरोह के पदाधिकारी की फैक्ट्री' में बेनकाब किया गया है। योग व्यवसायी रामदेव की पतंजली के शहद में चीनी की मिलावट तथा देसी घी व दूध की असलियत खुल गई। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी की हिन्दू युवा वाहिनी के मंडल सह प्रभारी अनूप वार्षणेय की हाथरस में पुलिस द्वारा नकली मसाला बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई जिसमें गधे की लीद, भूसा और एसिड की मिलावट की जा रही थी। स्पष्ट है कि ये तथाकथित देशभक्त और राष्ट्रवादी लोग अपने मुनाफ़े के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।